जनजाति क्षेत्र में बिजली कनैक्शन समय पर जारी करें : मुख्यमंत्री

अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद में मुख्यमंत्री भजनलाल ने सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया

जयपुर, 20 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं ट्राइबल सब प्लान एरिया (टी.एस.पी. क्षेत्र) के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वूपर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 से 30 जून तक चलाए जा रहे धरती आबा जन-भागीदारी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इसे सफल बनाएं। उन्होंने वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का शीघ्र निस्तारण कर अधिकारपत्र जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जलसंसाधन विभाग की परियोजनाओं तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की गतिविधियों में प्रगति लाने के निर्देश दिए, और जनजाति क्षेत्र में बिजली कनेक्शन समय पर जारी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टीएसपी क्षेत्र में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोगियों की पहचान और उपचार सहायता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा।

इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, विधायक समाराम, फूल सिंह मीणा, प्रताप लाल भील, श्रीमती शान्ता अमृत लाल मीणा, गोपीचंद मीणा, ललित मीणा, महेन्द्र पाल मीणा, हंसराज मीणा, राजेन्द्र मीणा, रामबिलास, शंकर लाल डेचा एवं मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक को संबोधित किया।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयन्ती पर 15 से 30 जून तक चलाये जा रहे, ''धरती आबा जन भागीदारी अभियान'' में जन प्रतिनिधियों को सक्रिय भागीदार निभाने को कहा।**

'महाप्रभु की धरती पर आना था इसलिए नहीं गया अमेरिका'

भुवनेश्वर, 20 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अमेरिका आने का राष्ट्रपति ट्रंप का निमंत्रण इस कारण स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें महाप्रभु की धरती ओडिशा आना था।

मोदी ने ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रम में कहा कि दो दिन पहले वह कनाडा में जी7 देशों की शिखर बैठक में भाग लेने गये थे और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन कर अमेरिका आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ट्रंप ने मुझ से कहा कि आप कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है।

'अंग्रेजी जंजीर नहीं जंजीर तोड़ने का जरिया है, यह शर्म नहीं शक्ति है'

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के, अंग्रेजी भाषा के खिलाफ दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा

- **राहुल ने कहा अगर आप अंग्रेजी सीख जाते हैं तो कहीं भी घुस सकते हैं। आपके लिए बड़ी नौकरियों के दरवाजे खुल सकते हैं।**
- **राहुल ने कहा, भाजपा व आरएसएस वाले नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखें।**

नई दिल्ली, 20 जून। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अंग्रेजी बोलने वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अंग्रेजी बांध नहीं, पुल है। अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है। अंग्रेजी जंजीर नहीं – जंजीरें तोड़ने का औजार है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, भाजपा-आरएसएस वाले नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ -लिखकर सवाल पूछें, आगे बढ़ें और बराबरी करें। आज के समय में अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मातृ भाषा – क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी और आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

राहुल ने कहा कि भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है – और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का, जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे।

राहुल ने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें वह बता रहे हैं कि अंग्रेजी एक हथियार है। आप अगर अंग्रेजी सीख जाते हैं तो कहीं भी घुस सकते हैं। आप अमेरिका, जापान और कहीं भी जा सकते हैं। आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अंग्रेजी के खिलाफ जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आपको करोड़ों रुपये की नौकरी मिले। वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद रहे।

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जल्द ही भारत में ऐसा समय आएगा जब अंग्रेजी बोलने वाले खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। किसी विदेशी भाषा में आप अपनी संस्कृति, धर्म और इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। गृहमंत्री ने यह बात आशुतोष अग्निहोत्री की किताब के विमोचन के मौके पर कही थी।

एयर इंडिया ने चार इंटरनैशन फ्लाइट्स सहित आठ फ्लाइट्स कैंसल कीं

नई दिल्ली, 20 जून। एअर इंडिया ने एक बार फिर अपनी कई उड़ान सेवाएं रद्द कर दी हैं। एयरलाइन की ओर से अब तक चार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों सहित आठ फ्लाइट्स को रद्द करने की सूचना दी गई है।

एयरलाइन ने बताया कि शुक्रवार को रखरखाव और परिचालन संबंधी कारणों से एअर इंडिया ने चार अंतरराष्ट्रीय सेवाओं सहित आठ उड़ानें रद्द कर दी हैं। यात्रियों के लिए जल्द से जल्द अपने गंतव्यों तक उड़ान भरने के लिए ग्राउंड पर उसकी टीमें वैकल्पिक व्यवस्था कर रही हैं।

एयरलाइन ने कहा कि उसने यात्रियों से, टिकट रद्द करने पर पूरे पैसों की वापसी या यात्रा को फिर से निर्धारित करने की पेशकश की है।

एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति अपनी वेबसाइट पर देखें या अपडेट के लिए ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करें। बयान में आगे कहा गया, ''विमानों पर बढ़ी जांच, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध और खराब मौसम के कारण हम कुछ व्यवधानों से जूझ रहे हैं, जिसके बारे में यात्रियों को उचित रूप से सूचित किया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति यहां हमारी वेबसाइट पर देखें।''

इससे पहले एअर इंडिया ने गुरुवार को कहा था कि 21 जून से 15 जुलाई के बीच 16 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानें कम की जाएंगी और तीन विदेशी गंतव्यों पर उड़ानें निलंबित रहेंगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा था कि इसका उद्देश्य यात्रियों को अंतिम समय में होने वाली असुविधा को कम करना है। दरअसल, अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइन ने अपने विमानों की जांच बढ़ा दी है और एहतियातन कई कदम उठा रही है।

'आरक्षण की 50 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में शामिल करने का आव्हान किया

उन्होंने कहा, यह काम 1994 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण की रक्षा के लिए किया गया था।

उन्होंने संविधान में संशोधन करने की भी मांग की ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की 50 सीमा को पार किया जा सके।

रमेश ने कहा कि यह सीमा पिछले छह दशकों में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के कारण ही लागू हुई है।

उन्होंने कहा, अनुच्छेद 15(5) निजी शैक्षिणक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। यह पिछले 11 वर्षों से लागू नहीं हो पाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए गए इस संवैधानिक संशोधन को मान्यता दी था।''

रमेश ने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से जुड़े इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएगी।

पासपोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पासपोर्ट तय समय में जारी करें। याचिकाकर्ता की शादी 2023 में हुई थी, लेकिन पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। तलाक का केस चल रहा है। रेवती ने इस साल अप्रैल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। जब उसका आवेदन आगे नहीं बढ़ा तो उसने जानकारी ली, जिसके बाद उसे बताया गया कि उसे फॉर्म-जे में पति के हस्ताक्षर लेने होंगे, तभी पासपोर्ट आवेदन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आरपीओ ने यह भी कहा कि चूंकि पति-पत्नी के बीच कोर्ट में विवाद चल रहा है, इसलिए यह हस्ताक्षर जरूरी हैं।

रेवती ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जज ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के विचार में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया पासपोर्ट आवेदन की स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी पत्नी को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले पति की अनुमति या उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जज ने कहा कि आरपीओ की यह मांग यह दिखाती है कि हमारे समाज में विवाहित महिलाओं को अब भी पति की संपत्ति की तरह देखा जाता है। यह चौंकाने वाली बात है कि पासपोर्ट ऑफिस पति की अनुमति और एक विशेष फॉर्म में उसके हस्ताक्षर पर ही पासपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा था। उन्होंने कहा कि जब पति-पत्नी के बीच रिश्ते पहले से ही बिगड़े हुए हैं, तब आरपीओ की ओर से पति के हस्ताक्षर की मांग करना याचिकाकर्ता से असंभव चीज की उम्मीद करने जैसा है।

राहुल गांधी, अब देश का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दीं और गुलदस्ते भेंट किए।

मुख्यधारा के समाचारपत्रों में उनके जन्मदिन पर पूरे पन्ने के विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित रहते हैं।

राहुल गांधी लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या और इस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की निष्क्रियता की बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर एक रोज़गार मेला आयोजित किया गया, जिसमें कई कंपनियों को आमंत्रित किया गया और 3000 से अधिक युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए।

संदेश साफ़ था, यदि विपक्ष के नेता पद पर रहते हुए वह इतना कुछ कर सकते हैं, तो यह समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में वह युवाओं और बेरोजगारों के लिए कितना ज्यादा कर सकते हैं।

राहुल गांधी जातीय जनगणना के अपने एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे अब सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, और यह उनके नेतृत्व के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

राहुल गांधी ने एक समिति गठित की है, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी और दलित नेता शामिल हैं। इस समिति के अध्यक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, जो इस एजेंडे को और आगे बढ़ाएंगे।

दिलचस्प बात यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही इस समिति के सदस्य हैं।

कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का यह आकलन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधार खिसक रहा है। भाजपा और संघ परिवार के भीतर गंभीर समस्याएं हैं। अमेरिका और डॉनल्ड ट्रंप अब नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं रहे।

इसके अलावा, बिहार को एनडीए से वापस जीतने की पूरी संभावना है, और इसका मुख्य कारण नीतीश कुमार को माना जा रहा है, जो एक कमज़ोर कड़ी बन गए हैं। सूत्रों का यह तक कहना है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाज़ी में हैं और उन्हें विश्वास है कि उनका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आधारित एजेंडा आने वाले समय में उन्हें बड़ा राजनीतिक लाभ दिलाएगा। यह राहुल गांधी 2004 के राहुल गांधी से एकदम अलग हैं, जो उस समय राजनीति की असल दुनिया और उसके तंत्र से पूरी तरह कटे हुए लगते थे।

राजनीति को स्वीकार करना उनके लिए एक लंबी प्रक्रिया रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह परिवार की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसका इंतज़ार उनकी मां सोनिया गांधी लंबे समय से कर रही थीं।

विशाखापट्टनम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से ज़्यादा लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश सरकार इस अवसर को यादगार बनाने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास का भी समन्वय कर रही है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत प्रतिभागियों को 50 लाख से ज़्यादा योग प्रमाणपत्र दिए जाएँगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह संस्करण देश की स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण बन जाएगा।

विमान हादसा: 223 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस प्रकार सिविल अस्पताल से कुल 204 शव सौंपे जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि जिन 223 मृतकों के डीएनए मैच पाए गए हैं, उनमें 168 भारतीय नागरिक, सात पुर्तगाली, 36 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई और 11 गैर-यात्री यानी स्थानीय लोग शामिल हैं। इनमें 15 शव हवाई मार्ग से तथा 189 शव सड़क मार्ग से उनके आवासों तक पहुंचाए गए।

इज़रायल खुशी मना रहा है, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एयर डिफैंस सिस्टम नष्ट कर दिया है जो कि अब तक ईरान के फोर्दो और नतांज जैसे परमाणु केन्द्रों को बचाए हुए था। इज़रायल की सफलता ने इन ठिकानों को असुरक्षित कर दिया है। पर इज़रायल की यह सफलता ईरान को अपनी रणनीति बदलने को बाध्य कर सकती है और वह अब पारम्परिक प्रतिरोध के बजाय अंधाधुंध प्रतिशोध की नीति अपना सकता है।

यह बदलाव पहले से ही दिखने लगा है। लेबनान में हिज़बुल्लाह ने सीमा पार हमले तेज कर दिए हैं, यमन में हूथियों ने सऊदी और इज़रायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले फिर से शुरू कर दिए हैं, और यूएई में तेल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों की रिपोर्ट सामने आई है, जिनके पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा है।

ईरान समर्थित तथाकथित 'प्रतिरोध धुरी' (एक्सिस ऑफ रैज़िस्टैंस) सक्रिय हो रही है, बहुत बड़े-बड़े हमलों से नहीं बल्कि छोटे-छोटे हमलों से, जो धीरे-धीरे नुकसान पहुँचाएं और डर पैदा करें।

इस बीच, खाड़ी देशों की राजशाहियों को एक नाज़ुक भू-राजनीतिक संतुलन साधना पड़ रहा है। सऊदी अरब और यूएई, भले ही ईरान को नियंत्रित करने के इज़रायली रणनीतिक लक्ष्य से सहमत हों, लेकिन वे खुद को पूर्ण युद्ध में झोंकने से बचना चाहते हैं।

2019 में अरामको रिफाइनरी पर हुए हमलों की यादें अभी भी ताज़ा हैं, और दोनों देशों ने चुपचाप इज़रायल और अमेरिका से संयम बरतने का आग्रह किया है, हालाँकि वे चुपचाप अपनी जमीन को पश्चिमी अभियानों के लिए लॉजिस्टिक आधार के रुप में इस्तेमाल होने दे रहे हैं।

इस पूरी स्थिति को वैश्विक शक्तियों की संभावित भागीदारी और जटिल बना रही है। यदि अमेरिका ईरान के, गहराई में स्थित परमाणु स्थलों पर सीधा हमला करता है, तो रूस या चीन की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, शायद सैन्य नहीं, लेकिन हथियारों की आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक विरोध, या दक्षिण चीन सागर जैसे इलाकों में गतिविधियों के जरिए।

इस तरह, इज़रायल की सामरिक (टैक्टिकल) जीत, रणनीतिक (स्ट्रैटेजिक) रूप से भारी पड़ सकती है। फिलहाल ईरान की पारंपरिक सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया है, लेकिन क्षेत्र को अस्थिर करने की उसकी क्षमता अब भी बरकरार है। यह इलाका एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहाँ असुरक्षा, आर्थिक कमज़ोरी और भू-राजनीतिक पुनर्गठन की आशंका है।

अगर इज़रायल और उसके सहयोगियों का लक्ष्य ईरान के परमाणु खतरे को समाप्त करना है, तो उन्हें यह समझना होगा कि ईरान को सैन्य रूप से कमज़ोर करना तो आसान काम था। असली चुनौती अब उस क्षेत्रीय तूफ़ान को संभालने की है जो इस कार्रवाई के बाद उठ सकता है, एक ऐसा संकट जिसे दुनिया की तेल-निर्भर अर्थव्यवस्थाएँ बिल्कुल भी झेल नहीं सकतीं।

ईडी ने वरिष्ठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायाधीश को पत्र लिखा, जिसमें ईडी की कार्रवाई की निंदा की गई और वेणुगोपाल को समन जारी करने के मामले में सीजेआई से स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया गया। पत्र में कहा गया कि ईडी की इस कार्रवाई का ''कानूनी पेशे की स्वतंत्रता'' और ''वकील-क्लाइंट गोपनीयता के मौलिक सिद्धांत'' पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पत्र में निम्नलिखित अनुरोध किए गए।

पहला, कानूनी पेशेवरों द्वारा अच्छी भावना से दी गई सलाह के लिए उन्हें दिए गए सम्मन की वैधता व औचित्य की जांच की जाए।

दूसरा, वकील-क्लाइंट गोपनीयता के और अधिक क्षरण को रोकने तथा बार की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उचित दिशा-निर्देश निर्धारित करना। तत्पश्चात, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर (मुंबई) ने तत्काल प्रभाव से उक्त समन को वापस ले लिया, जिसके अनुसार वेणुगोपाल को 24 जून को एजेंसी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

क्या वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **पश्चिमी देशों ने बाद में दो बार, पश्चिमी देशों की समर्थक सरकारें बनाने का प्रयास किया था ईरान में, पर, दोनों बार मुँह की खायी थी।**
- **क्या इन असफल प्रयासों से सबक लेकर अमेरिका दोबारा ईरान में अपनी पिट्ठु सरकार बैठाने का प्रयास करने से पहले गंभीरता से सोचेगा।**

लेकिन इसने लंदन और वॉशिंगटन में खलबली मचा दी।

ब्रिटेन, जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था, ने शाह के साथ मिलकर, मोसद्देग को संसदीय माध्यमों से हटाने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। इसके बाद उन्होंने गुप्त तरीकों की ओर रुख किया।

''एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका'' के अनुसार, मोसद्देग की साम्यवाद विरोधी विचारधारा के बावजूद, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को यह विश्वास दिलाया कि वे सोवियत प्रभाव के प्रति संवेदनशील हैं। तथा इसलिए अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए।

सीआईए ने ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेन्स सर्विस, जिसे एम आई 6 के नाम से जाना जाता था, के साथ मिलकर मोसद्देग को हटाने के लिए एक गुप्त अभियान शुरू किया।

सीआईए ने इसे ''टी पी ए जे ए एक्स'' नाम दिया और एमआई6 ने इसे ''ऑपरेशन बूट'' कहा।

इस तख्तापलट की तैयारी के दौरान, सीआईए और एमआई6 ने मोसद्देग विरोधी माहौल तैयार किया। उन्होंने दुष्प्रचार अभियान चलाया, प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक नेताओं को डराया-धमकाया और जनता में अशांति फैलाई।

''द गार्जियन'' की रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में सार्वजनिक किए गए सीआईए दस्तावेज़ों में इस तख्तापलट का एक अंदरूनी मसौदा इतिहास भी है, जिसका शीर्षक है: ''ईरान में एक पश्चिम समर्थक सरकार को स्थापित करने का अभियान''। इसका उद्देश्य था: ''कानूनी या गैर-कानूनी तरीकों से मोसद्देग सरकार को हटाना और उसकी जगह शाह के नेतृत्व में पश्चिम समर्थक बनाकर, जनरल ज़ाहेदी को प्रधानमंत्री बनाना।''

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 1953 में तेहरान में शाह समर्थक प्रदर्शनकारियों जिसे सेना का समर्थन प्राप्त था तथा अमेरिका और ब्रिटेन से वित्तपोषित थे-के बीच झड़पें हुईं, जिनमें लगभग 300 लोग मारे गए।

यह तख्तापलट सफल रहा। मोसद्देग को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें तीन साल जेल में और फिर जीवनभर नजरबंद रखा गया। जनरल फज़ल्लाह ज़ाहेदी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

सीआईए ने ज़ाहेदी को सत्ता संभालने के दो दिन के भीतर 50 लाख डॉलर की गुप्त मदद भी दी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908